



## नागरिक केंद्रित डिजिटलीकरण

यह एडिटरियल 03/11/2022 को 'लाइवमटि' में प्रकाशित "G20 offers India a chance to be the architect of a new digital economy" लेख पर आधारित है। इसमें भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था में नागरिक केंद्रीयता की आवश्यकता के बारे में चर्चा की गई है।

### संदर्भ

डिजिटल अवसंरचना का उभार नागरिकों के लिये बजिली, जल और सड़क जैसी पारंपरिक अवसंरचना आवश्यकताओं के समान या उससे भी अधिक महत्वपूर्ण अवसंरचना आवश्यकता के रूप में हुआ है। कोविड-19 महामारी ने न केवल वैश्विक व्यवस्था को बदल दिया है, बल्कि इसने लगातार बढ़ती डिजिटल अवसंरचना को भी गति प्रदान की है।

- किसी समाज के कार्यकरण और उसके नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता के लिये डिजिटल अवसंरचना अनिवार्य हो गई है। भारत में लगभग आधा बलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और बड़ी संख्या में स्वदेशी डिजिटल सेवाओं के साथ अनुमान है कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का व्यापक रूपांतरण होगा।
- किसी डिजिटल अर्थव्यवस्था की सफलता के लिये आवश्यक है कि यह महत्वपूर्ण सेवाओं के लिये सभी नागरिकों को एकसमान अवसर और पहुँच प्रदान करे। भारत को अपनी शक्ति की पहचान करनी होगी। उसे एक नागरिक केंद्रित डिजिटल अर्थव्यवस्था हेतु एक ढाँचे के निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।

## भारत की डिजिटल क्रांति में नागरिक केंद्रीयता की वर्तमान स्थिति

- भारत सरकार का [डिजिटल इंडिया कार्यक्रम](#) देश के कोने-कोने तक हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। इसके अलावा, यह नागरिकों की सुविधा और शासन में सुधार के लिये विभिन्न प्रकार की डिजिटल सेवाओं की स्थापना का लक्ष्य रखता है।
- **डिजिटल इंडिया के तहत शामिल कुछ प्रमुख परिवर्तनकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं:**
  - **MyGov:** इसने एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान कर देश में नागरिक संलग्नता एवं भागीदारी शासन की सुदृढ़ नींव रखी है, जहाँ नागरिक सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के संबंध में अपने विचार साझा कर सकते हैं।
  - **यूनफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface- UPI):** यह मोबाइल फोन के माध्यम से अंतर-बैंक लेनदेन की सुविधा के लिये [भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम](#) (National Payments Corporation of India- NPCI) द्वारा विकसित एक तत्काल वास्तविक समय भुगतान प्रणाली (instant real-time payment system) है।
    - वर्ष 2021 में UPI के माध्यम से लगभग 39 बलियन लेनदेन हुए (कुल राशि 940 बलियन अमेरिकी डॉलर)। यह राशि भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 31% के बराबर है।
  - **डिजिटल लॉकर/डिजिटलॉकर(DigiLocker):** यह उपयोगकर्ताओं को उनके दस्तावेज़ सत्यापन एवं भंडारण हेतु डिजिटल स्पेस प्रदान कर पेपरलेस शासन को सक्षम कर रहा है।
  - **मेघराज (MeghRaj):** क्लाउड कंप्यूटिंग के उपयोग और इसके लाभों का दोहन करने के लिये सरकार ने जीआई क्लाउड (GI Cloud) की एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है जिसे मेघराज नाम दिया गया है।
    - इस पहल का मुख्य ध्येय सरकार के ICT व्यय को इष्टतम करते हुए देश में ई-सेवाओं के वितरण में तेज़ी लाना है।
  - **स्वयं और स्वयंप्रभा:** स्वयं (SWAYAM) पोर्टल 2,000 से अधिक खुले पाठ्यक्रम प्रदान कर शिक्षा प्रणाली को रूपांतरित करने की ओर अग्रसर है। स्वयंप्रभा (SWAYAMPRAKHA) उच्च गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिये समर्पित 32 DTH टीवी चैनलों का एक समूह है।

## भारत में नागरिक-केंद्रित डिजिटलीकरण के मार्ग की प्रमुख बाधाएँ

- **डिजिटलीकरण प्रेरित केंद्रीकरण:** चूँकि डिजिटल प्रौद्योगिकी शासन को एकीकृत करती है और केंद्र सरकार अधिकांश डेटा धारण करती है, केंद्रीकरण (centralisation) केंद्र और राज्यों के बीच कलह का कारण बन सकता है।
  - यह तब और अधिक प्रासंगिक बन जाता है जब वित्तीय सहायता के लिये एक पूर्व शर्त के रूप में डेटा साझाकरण के लिये केंद्र सरकार द्वारा



- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 3
- (C) केवल 2 और 3
- (D) 1, 2 और 3

उत्तर: (B)

????? ???? ???? ???? ?

Q. "चौथी औद्योगिक क्रांति (डिजिटल क्रांति) के उद्भव ने सरकार के अभिन्न अंग के रूप में ई-गवर्नेंस की शुरुआत की है"। वचिर-वमिरश कीजयि। (वर्ष 2020)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/citizen-centric-digital-revolution>

